(i) to finalise a list of critical indicators of child survival and development which could be implemented in a phased manner; and

(ii) to prepare a work plan specifying the scope and details of the activities in different stages with targeted outputs, participating agents (institutions and persons responsible), time frame for implementation, mid-course review and conclusion of each state and budget requirements.

The Government has accepted the recommendation.

लोहे के स्लीपरों की ढुलाई के लिये टिस्को द्वारा उपयोग किये गये वैगन

263. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977 से 1980 के बीच टिस्को जमशेदपुर ने रेल के वैगनों में लोहे के स्लीपरों को लाद कर भेजा था और उन्हें खाली दिखाकर काला बाजारी से करोड़ों रुपया कमाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों और मैसर्स टिस्को के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे वैगनों की संख्या कितनी है और इन वैगनों में अनुमानतः लोहे के कितने स्लीपरों का लदान किया गया और उसकी कीमत क्या थी ; और

(घ) क्या सरकार यह पता लगाने के लिये कि क्या यह काम अभी भी जारी है, कोई जांच करने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) 1977 से 1980 तक टिस्को द्वारा लोहे के स्लीपरों की जाली बुकिंग और रेलवे और टिस्को के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये किसी मामले की सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

264. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्रीमती कनक मुखर्जी :
श्री चिमनभाई मेहता :
श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या थे ;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ था ; और

(घ) क्या सम्मेलन में हुई चर्चा का आधार देश की भावनात्मक एकता और अखण्डता था ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जो 23–24 जनवरी, 1986 को हुआ था, ने नई शिक्षा नीति से संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा की और निम्नलिखित विषयों पर बल दिया :

(1) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति का सृजन करना ।

(2) गैर-औपचारिक शिक्षा सहित प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना ।

(3) माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायीकरण ।

(4) प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा ।

(5) उच्चतर शिक्षा के लिये पहुंच पाठ्यक्रमों का डिजाइन तथा उनकी संरचना तैयार करना, अनुसंधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार आदि की भूमिका ।

(6) शिक्षकों के निष्पादन में सुधार से संबंधित शिक्षक-प्रशिक्षण ।

(7) भाषा-नीति ।

(8) परीक्षा सुधार ।

(9) लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा ।

(10) खेल और शारीरिक शिक्षा ।

(11) शैक्षिक आयोजना और प्रबन्ध ।

(12) तकनीकी शिक्षा की परिवर्तनशील भूमिका ।

(13) शिक्षा के संसाधनों को गतिशील बनाना ।

सम्मेलन ने एक सामान्य कोर पाठ्यचर्या को अपनाने की सिफारिश की जसमें राष्ट्रीय मान्यता के पोषण तथा देश की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिये अनिवार्य कुछ कोर तत्वों से संबंधित विषय-वस्तु शामिल होगी । सम्मेलन ने, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करन , शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने और विशेष रूप से जन-जातीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में गैर-अध्ययनशील विषयों को शामिल करने की पद्धति का विस्तार करने, निरक्षरता का उन्मूलन, औपचारिक शिक्षा पद्धति में वर्तमान संस्थाओं का विस्तार से समीकरण करने के लिये बल देने की ओर स्थानान्तरित करना—यह विस्तार वंचित क्षेत्रों और वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित है, शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शिक्षण विधियों, आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति , माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सुधार करना, प्रत्येक जिले में माडल स्कूलों की स्थापना करना तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी चर्चा की ।

नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गयी । आशा है कि नीति संबंधी अन्तिम प्रारूप बाद में अप्रैल, 1986 में संसद में प्रस्तुत किया जायेगा ।

Linking Madurai and Trivandrum through National Highway

265. SHRI M.M. JACOB: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Government of Kerala for the construction of a National Highway connecting Madurai (Tamil Nadu) and Trivandrum via Moovattupuzha in Kerala;

(b) if so, by when this highway is likely to be constructed;

(c) if the answer to part (a) above be in negative, whether Government propose to link Madurai to Trivandrum and if so in what manner; and

(d) what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (d) Since the beginning of the 6th Five Year Plan, the Kerala Government have been forwarding proposals for declaring certain State Roads as National Highways which *Inter-alia* included the Madurai-Muvattupuzha-Kottayam-Trivandrum Road. But owing to financial stringency, it has not been possible to accede to this request. However, loan assistance to the tune of Rs. 175 lakhs was provided in the 6th Plan for undertaking essential improvement works to the road in question. In the Seventh Five Year Plan also, there is no scope for inclusion of this road in the National Highways system or to render further assistance under the Central Sector Road Programme on account of inadequate allocations earmarked for the purpose.